P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-6, ISSUE-4, May- Supplementary Issue - 2018
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड सरकार की नीति एवं योजना : एक विश्लेषण

Please Send one passport size photo in our mail id

नीलू कुमारी
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
वी0श0के0च0 राजकीय स्नान0महाविद्यालय,
डाकपत्थमर, विकासनगर, देहरादून

सारांश

किसी भी देश में रोजगार का आकार बहुत कुछ उसके विकास के स्तर पर निर्भर करता है। किन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था का जिस तरह से विकास हुआ है उससे रोजगार की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना संभव नहीं हो सका है। क्योंकि जिस दर से विकास एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हई है उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या एवं शिक्षा में वृद्धि हुई है। शिक्षित व्यक्तियों के पास भी व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है जिस कारण से उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि चाहे व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित उनके कौशल विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करने पर ज्यादा जोर दिया जाये ताकि उन्हें राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने एवं वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सफलता मिल सके। कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति जहां अपने लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करने में सक्षम हो पाता है वहीं दूसरे के लिए भी रोजगार का सृजन कर सकता है।

कौशल विकास के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कई कदम उठाये गये हैं। न सिर्फ भारत सरकार के द्वारा बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी इस क्षेत्र में कई प्रयास किये गये हैं। इस पेपर में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए किए गये प्रयासों का विश्लेषण किया गया है। उत्तराखण्ड द्वारा हाल के वर्षों मेंकिये गये प्रयासों में मुख्य रूप से उत्तराखण्ड कौशल विकास सोसाइटी, उत्तराखण्ड कौंसिल फॉर बायोटेक्नोलोजी, दैवीय आपदा क्षेत्र के लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। हालांकि ये विभिन्न प्रयास अपनी उपादेयता स्थापित करने में निरन्तर अग्रसर हैं। लेकिन इस दिशा में अभी काफी प्रयास की आवश्यकता है ताकि बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करने के साथ–साथ पहाड़ से मैदान की ओर हो रहे निरंतर पलायन को रोका जा सकें।

मुख्य शब्दः

प्रस्तावना

किसी भी देश के आर्थिक विकास में मानव संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और मानव संसाधन की प्रगति तथा विकास में कौशल व ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी देश की श्रमशक्ति कुशल है तो उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। श्रमशक्ति अशिक्षित, अकुशल होने या उसका उपयोग अनुपयुक्त तरीके से करने पर ये अर्थव्यवस्था के लिए बोझ भी बन जाते हैं। कौशल विकास एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अन्दर छुपी हुई कार्यकुशलता एवं योगयता को उभारकर उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। आज जब भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ रही है ऐसी स्थिति में अपने लिए स्वरोजगार स्थापित करने, रोजगार का सृजन करने एवं वैश्विक प्रतियोगिता में ठहर पाने के लिए मानव संसाधन का कुशल एवं प्रशिक्षित होना आवश्यक है। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के द्वारा औद्योगिक जगत की कुशल श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति के बीच सामंजस्य भी प्रदान किया जा सकता है क्योंकि भारतीय श्रमशक्ति के बहुत छोटे से अंश को औपचारिक कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त है। जो लोग शिक्षित हैं उनके पास भी व्यावसायिक एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण का अभाव है। यही कारण है कि देश के कई क्षेत्रों को कुशल श्रमिकों की उपयुक्त मात्रा में उपलब्धि नहीं हो पाती जिसके कारण उत्पादकता कम रहती है। दूसरी ओर निर्धन एवं शिक्षित लोगों के बीच कार्य अवसरों की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार असंगठित क्षेत्र में अनियमित रोजगार अवसरों के लिए आपस में प्रतिस्पर्दा करते दिखाई देते हैं। असंगठित क्षेत्र में भी अनियमित रोजगार,

कम मजदूरी तथा शोषणकारी प्रकृतियाँ मौजूद हैं। बहुत से श्रमिक शहरी क्षेत्रों में पालयन कर जाते हैं, जहां उन्हें अमानवीय दशाओं में काम करना पड़ता हैं। मांग एवं पूर्ति की इन असमानताओं को दूर कर भारतीय नियोजकों तथा वैश्विक नियोजकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण निर्धनों को कौशल प्रदान कर उनकी कार्य योग्यताओं को बढ़ाने की काफी आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के बाद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य के लिए भी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा कई प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम चलाये गये हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए नई–नई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रम को संचालित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा एवं विकास प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयास किये जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षित व्यक्तियों के लिए भी कई स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं में चलाये गये हैं। खासकर बारहवीं योजना में बढ़ती हुई जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए योजना में कौशल विकास पर जोर दिया गया है। जिसमें 50 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही "भारत निर्माण" कार्यक्रम का उद्देशय विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है ताकि इस कौशल प्राप्त व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन एवं मांग पैदा हो सके। इसी तरह "कौशल भारत" का संबंध उच्च कौशल प्राप्त श्रमशक्ति तैयार करना है जो औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो ताकि उत्पादकता में सुधार किया जा सके जिससे आय, उत्पादन रोजगार एवं आर्थिक विकास की गति तेज जो सके। इससे भूमि पर जनसंख्या का दबाव एवं गरीबी भी दूर होगी।

अध्ययन का उद्देश्य

इस पेपर का उद्देश्य रोजगार प्राप्ति हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विश्लेषण करना है।

अनुसंधान विधि

यह पेपर द्वितीयक समंक पर आधारित है। द्वितीयक समंक मुख्य रूप से इन्टरनेट, विभिन्न शोध पत्रों, एव किताबों से लिए गये हैं।

भारत सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अलग कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 23 सितंबर, 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (क्क्न्–ळज्ञल), कौशल विकास एवं उद्यमिताकी राष्ट्रीय नीति 2015 आदि प्रारंभ की है। इन विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य जनाधिक्य का लाभ उठाकर उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल करना, औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप श्रमशक्ति तैयार करना तथा रोजगार एवं उत्पादकता में सुधार कर आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इस संदर्भ में इस पेपर में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाये गये विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम का विश्लेषण किया गया है। पुराने समय से ही उत्तराख्ण्ड राज्य शिक्षा का केन्द्र रहा है। यहाँ की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 78.8 प्रतिशत है जो भारत की साक्षरता दर 71.62 प्रतिशत से अधिक है। यहाँ की विकास दर 18.81 प्रतिशत एवं प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः भारत की विकास दर 17.64 प्रतिशत एवं प्रतिव्यक्ति आय 74920 से अधिक है। किन्तु साक्षरता दर, विकास दर, प्रतिव्यक्ति आय एवं अन्य कई समृद्धि सूचकों के बावजूद भी यहाँ गरीबी की दरें भारत की गरीबी की दर से अधिक है। लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है एवं रोजगार की तलाश में युवकों का पहाड़ से मैदान की ओर पलायन जारी है। रोजगार प्रदान कर गरीबी दूर करने के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की और संबंधित मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा कौशल प्रदान करने के लिए कदम उठाये हैं जो निम्नवत हैं–

तालिका–1

सरकार द्वारा चलाई गई कौशल विकास योजनायें

मंत्रालय/विभाग	योजनायें/संस्थान	मुख्य बिन्दु
कृषि विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डेयरी उद्मियों के लिए बीग डेयरी स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	कृषिकों को प्रशिक्षण प्रदान करनाख् डेयरी उद्मियों का प्रोत्साहित करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
श्रम और रोजगार मंत्रालय	ग्रामीण रोजगार सृजन योजना (REGP), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGR), ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षण (TRYSEM)	लोगों को उनके ज्ञान एवं कौशल का व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए उच्च डिप्लोगा एवं डिग्री का सर्टिफिकेट।
वस्त्र मंत्रालय	समन्वित कौशल विकास योजना (ISDS),	कौशल विकास प्रशिक्षण योजना द्वारा टेक्सटाइल में कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना।
MMSME विकास संस्थान हल्द्वानी	MSME विकास संस्थान द्वारा DC प्रारंभ किए गए कौशल विकास को लागू करना।	उत्तराखण्ड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए समर्पित इसमें 2011–12 के दौरान 2321 व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया

		गया ।
ग्रामीण विकास मंत्रालय	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (SGSY)	SC,ST महिलाओं एवं गरीबों पर मुख्य रूप से लागू है।
पर्यटन विकास	उत्तराखण् पर्यटन विकास मास्टर प्लान	पर्यटन के विकास के लिए Strategic Spatial

स्रोतः NSDC

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

तालिका–02
प्राथमिक क्षेत्र

क्षेत्र	लक्षित समूह	योजनायें
कृषि, फूलों की खेती एवं बागवानी	किसान	पिण्डर घाटी (बागेश्वर, चमोली) में कृषि विकास योजनायें, कृषि तकनीकी पर प्रशिक्षण, जैविक कृषि, नर्सरी प्रशिक्षण, फली हाउस बनाने इत्यादी के लिए प्रशिक्षण।
पशुपालन एवं सहायक सेवायें	कृषक, अनुसूचित जाति एवे जनजाति	राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के द्वारा पशुओं के प्रजनन जगह का प्रशिक्षण एवं कृषकों का ओरिएन्टेशन।
उन प्रसंस्करण (Processing)	जनजाति, सामान्य	उन प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, छटनी एवं बाजार प्रबंधन से सम्बंधित प्रशिक्षण।
जैविक कृषि	किसान	मजरवाली (रानीखेती) अल्मोड़ा में जैविक कृषि से संबंधित प्रशिक्षण (औऐनिक कमोडिटी बोर्ड के अन्तर्गत)

तालिका–03
द्वितीयक क्षेत्र

क्षेत्र	लक्षित समूह	योजनायें
खादी	शिल्पी	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, रंगाई, धुनाई एवं डिजाइन के लिए मार्केटिंग प्रशिक्षण।
फूड प्रसंस्करण	किसान, उद्यमी	जिला औद्योगिक केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, फल और सब्जियों के लिए सोर ड्राइंग सिस्टम ।
उद्योग विनिर्माण ऑटोमोबाईल	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आई०टी०आई) एवं पॉलीटेक्निक के विद्यार्थी	प्रशिक्षण एवं इन्टर्नशिप

तालिका–04
तृतीयक क्षेत्र

क्षेत्र	लक्षित समूह	योजनायें
पर्यटन आतिथ्य एवं व्यापार	सामान्य	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना, साहसिक क्रीड़ा, प्राकृतिक पर्यटन, पर्यटन गाइड इत्यादि के लिए प्रशिक्षण
शिक्षा एवं व्यावसायिक सेवा	शिक्षक	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्रोतः NSDC

उत्तराखण्ड सरकार ने प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने एवं लोगों की बेरोजगादी एवं गरीबी दूर करने के दिशा में विभिन्न कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये हैं। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषकों को कृषि की नई तकनीक एवं विक्रय से संबंधित प्रशिक्षण, प्रदान किये जाते हैं ताकि उनकी उत्पादकता में सुधार हो एवं गरीबी दूर हो सके। फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इस प्रकार रही है।

तालिका–05
उत्तराखण्ड में फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
2001-02	8864	2009-10	10832
2002-03	9718	2010-11	11430
2003-04	10954	2011-12	10892
2004-05	10954	2012-13	13492
2005-06	11062	2013-14	9078
2006-07	11795	2014-15	8537
2007-08	12644	2015-16	10273
2008-09	16764		

स्रोतः. उद्यान निदेशालय उत्तराखण्ड

द्वितीयक क्षेत्र में हैंडलूम, खादी, हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं लोगों में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना तथा रंगाई, धुनाई, डिजाइन एवं मार्केटिंग के प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं। उत्तराखण्ड में खादी एवं ग्रामोद्योग में 2008–09, एवं 2010–11 के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों एवं रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार हैः–

तालिकाः 06

उत्तराखण्ड में खादी एवं ग्रामोद्योग में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
2008-09	727	2850
2009-10	1210	3750
2010-11	1030	5191
2013-14	1030	4059
2014-15	1603	3955
2015-16	975	3299

स्रोतः– उत्तराखण्ड खादी एवं गोमोद्योग बोर्ड

इसके अतिरिक्त फूड प्रसंस्करण के लिए किसानों एवं उद्यमियों को जिला औद्योगिक केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उद्योग, विनिर्माण एवं ऑटोमोबाईल के क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार एवं अल्प औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) एवं पॉलीटेक्निक के माध्यम से युवाओं को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं। जिनमें मुख्य रूप से निम्न हैः–

तालिकाः 07

उत्तराखण्ड में प्रावैधिक, औद्योगिक एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश (संख्या)

क्रम सं०	विभाग	2008-09	2009-10	2010-11	2013-14	2014-15	2015-16
1.	प्रावैधिक शिक्षण संस्थान (क)संख्या (ख)प्रवेश क्षमता (ग)वास्तविक प्रवेश	 35 4260 3736	 37 4320 4053	 40 4320 10725	 52 9252 10144	 53 13931 10383	 70 16659 14429
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (क) संख्या (ख)प्रवेश क्षमता (ग)वास्तविक प्रवेश	 106 6424 6666	 106 10388 6275	 115 1100 7047	 161 14661 9835	 174 10111 6364	 179 17092 10232
3.	शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (क) संख्या (ख)प्रवेश क्षमता (ग)वास्तविक प्रवेश	 13 2498 2498	 13 1300 1300	 13 1300 1300	 13 650 650	 13 1216 1075	 13 708 481
4.	इन्जिनियरिंग कॉलेज (क) संख्या (ख)प्रवेश क्षमता (ग)वास्तविक प्रवेश	 34 600 548	 34 660 623	 27 9867 7497	 39 10050 5196	 29 9810 5445	 25 8520 5078
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की (क) संख्या (ख)प्रवेश क्षमता (ग)वास्तविक प्रवेश	 1 723 1527	 1 1983 1790	 1 2240 2007	 1 1130 1126	 1 2095 2024	 1 2060 2012

स्रोतः– प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्व विद्यालय, उत्तराखण्ड आई०आई०टी० रूड़की।

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि प्रावैधिक शिक्षण संस्थान में 2008–09 में जहां 3736 छात्रों को प्रवेश दिया गया था वह 2010–11 में बढ़कर 10. 725एवं 2015–16 में 14429 लाख हो गई। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पर्यटन के क्षेत्र में क्रीड़ा एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में साहसिक क्रीड़ा अधिकारियों को नियुक्ति की है जो स्थानीय लोगों को ट्रेकिंग, माइन्टेनिंग, जलक्रीड़ा आदि का प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति पर्यटकों को गाइड करते हैं।

प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या 2008–09 में 6666 से बढ़कर 7047 एवं 2015–16 में 10232 हो गई। हालांकि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई परंतु इंजिनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पानेवालों की संख्या 2008–09में 548 के मुकाबले लगभग बारह गुना होकर

7497 हो गई। इस तरह तकनीकी प्रशिक्षण पाने वाले की संख्या में भी क्रमशः वृद्धि होती गई है। तृतीयक क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण पर्यटन आतिथ्य एवं व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए गये हैं। खासकर इस क्षेत्र में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना द्वारा पर्यटन से संबंधित प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान किए जाते हैं।

इसमें अतिरिक्त उत्तराखण्ड में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लाभार्थ भी कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं इसके अन्तर्गत 2009–10 में 416 युवाओं को तथा भूतपूर्व सैनिकोंध् आश्रितों को रिफ्रेशर सह रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 870 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था। वहीं 2015–16 में यह संख्या क्रमशः 388 एवं 413 थी।

स्रोतः सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में कई संस्थाओं की स्थापना की गई है। जिनमें मुख्य रूप से है– (1) उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमेंट मिशन :– इस सोसाइटी की शुरूआत 12 फरवरी, 2013 को हुआ। इसकी स्थापना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य है– उत्तराखण्ड के अप्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षित करना और जो पहले से प्रशिक्षित हैं उनको और भी ज्यादा उन्नत करना। सरकार का उद्देश्य इसके अन्तर्गत 6.5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। इसके लिए इस सोसाइटी ने पूरे उत्तराखण्ड में कई केन्द्र खोले हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

इनमें देहरादून में स्वरोजगार के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण, टिहरी में कौशल विकास प्रशिक्षण कैम्प, युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण, टिहरी गढ़वाल में मुफ्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण कैम्प, देहरादून और अल्मोड़ा में पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सैनिक भर्ती के पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना आदि मुख्य है।

उत्तरांचल कौसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी

यह उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा नवम्बर 2014 में स्थापित एक स्वायत्र संस्थान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार एवं आय प्राप्ति के लिए बायोटेक्नोलॉजी तकनीकों के प्रति जागरूक करना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, खासकर महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार प्राप्त करने की दिशा में अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अन्तर्गत दी जाने वाले प्रशिक्षण में बायोफोरमेटिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, कैश क्रोप कल्टीवेसन, प्लांट टिशू कल्चर, बायोफर्टिलाइजर, बायो इनर्जी इत्यादि मुख्य है। इन प्रशिक्षण से राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त भी सरकार द्वारा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कई कार्य किये गये हैं। 2017–18 में 11,900 युवाओं को 32 तरह के प्रशिक्षण दिये गए हैं । (हिंदुस्तान 21 अप्रैल 2018)किन्तु इसके बावजूद भी छैक्ब के एक अनुमान के अनुसार जहां इसके कुशल व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर कुशल व्यक्तियों की ओद्धयोगिक मांग में वृद्धि के कारण मांग एवं पूर्ति के बीच एक असमानता बनी रहेगी । इसे हम निम्न तालिका 08 में देख सकते हैं –

तालिका 08

उत्तराखंड में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की औद्धयोगिक मांग एवं पूर्ति में अंतर के अनुमान (लाख में) 2012–22

	मानव संसाधन की आवश्यकता में वृद्धि	मानव संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि	मानव संसाधन की उपलब्धता एवं आवश्यकता में अंतर
कुशल	7.04	4.80	2.26
अर्धकुशल	4.32	3.11	1.21
अल्पकुशल	9.22	17.45	8.23

स्रोतः नेशनल स्किल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन(NSDC)

निष्कर्ष

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न योजनायें चलाई गई हैं। इन विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या को विकास प्रक्रिया में शामिल करके औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप श्रमशक्ति तैयार करना तथा रोजगार एवं उत्पादकता में सुधार कर राज्य की आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इस संबंध में छैक्ब की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड में 2012–22 के बीच औद्योगिक क्षेत्रों को लगभग 7.06 लाख कुशल श्रम एवं 4.32 लाख अर्धकुशल की आवश्यकता होगी जबकि उसकी पूर्ति क्रमशः मात्र 4. 80 एवं 3.11 लाख ही हो पाएगी। यानी इतने बचे हुए लोगों को कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही 8.23 लाख अल्प कुशल व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। अतः कहा जा सकता है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा युवाओं को कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में किये गये प्रयास अपनी उपादेयता स्थापित करने में काफी हद तक सक्षम रहा है। लेकिन इस दिशा में अभी काफी प्रयास करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *Statistical Diary] Uttarakhand] 2010&11] 2016&17-*
2. *Uttarakhand Skill Corp Presentation pptÛ… www-nsdcindia-org>default>files>files*
3. *Uttaranchal Free Skill govt&jobs-uttaranchal-com>uksdum*
4. *ucb-uk-gov-in>uploads>2015>07>sh…-*
5. *Vasant Desai] ÞSmall&Scale Industries and Entrepreneurshipß& In the Twenty&First Century] Himalayan Publication] p&251-*
6. *Hindustan Newspaper – 24th January 2017] 21st April 2018-*
7. *http%//www-skilldevelopment-gov-in-skill&landscape-in-india*